



पंजीकृत

कार्यालय महालेखाकार (ले० व हक०) द्वितीय  
20 सरोजनी नायडू मार्ग उ०प्र० प्रयागराज

Phones: Off. 2622625-26

Fax: 0532-2624402

३०९१३

पत्रांक:-पेंशन विविध/LID-29170, 30012, 27149, 26585-  
दिनांक:-

सेवा मे,

मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी

सर्वोच्च न्यायालय के  
ई-सेल द्वारा भेजा गया

विषय :- अन्य राज्यों के राज्य कर्मचारियों के पेंशन /पारिवारिक पेंशन में मंहगाई राहत का भुगतान ।

महोदय,

इस कार्यालय के पत्रांक पेंशन विविध/मंहगाई राहत /अन्य प्रान्त/ दिनांक के कम में मैं इस पत्र के साथ निम्नलिखित राज्यों से प्राप्त पेंशन /पारिवारिक पेंशन में मंहगाई राहत सम्बन्धी शासनादेशों की प्रतियों प्रेषित कर रहा हूँ, जिसके अनुसार सम्बन्धित राज्य की पेंशन/पारिवारिक पेंशन आदि में मंहगाई राहत की दर एवं प्रभावी तिथि निम्नानुसार होगी:-

क्रमांक	राज्य का नाम	विषय /दर/प्रभावी तिथि	शासनादेश का संदर्भ
1	WEST BENGAL	1. Ex-gratia grant for the year 2021-22 to the pensioners/family pensioners of Ex-Management Staff of North Bengal Medical College & Burdwan Medical College. 2. Grant of Dearness Relief to the Bihar Government pensioners/family pensioners with effect from 01.01.2022	1. Ref No. Circular No. Pcn.Co-ordn/258/Vol-II/217 Vol-II/70 Dated 14.07.2022 2. Ref No. Circular No. Pen.Co-ordn/Bihar/Vol-IX/DR-71 Dated 15.07.2022
2	UTTARAKHAND	1. राज्य सरकार के ऐसे सिविल/ पारिवारिक पेंशनर जिनकी पेंशन सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित की गयी है, को मंहगाई राहत की स्वीकृति । 2. राज्य सरकार के ऐसे सिविल / पारिवारिक पेंशनर जिनकी पेंशन सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित नहीं की गयी है, को मंहगाई राहत की स्वीकृति । 3. राज्य सरकार के ऐसे सिविल / पारिवारिक पेंशनर जिनकी पेंशन छठवें / सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित नहीं की गयी है, को मंहगाई राहत की स्वीकृति । 4. पांचवें केन्द्रीय वेतनमान में वेतन आहरित कर रहे राज्य सरकार और स्वायत्त निकायों / उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए मंहगाई भत्ते का 01 जनवरी 2021 बढ़ी हुई दर पर भुगतान । 5. छठवें केन्द्रीय वेतनमान में वेतन आहरित कर रहे राज्य सरकार और स्वायत्त निकायों / उपक्रमों के	Ref No.GO No.XXVII (7)02/2016 Dated 31.05.2022

		कर्मचारियों के लिए मंहगाई भत्ते का 01 जनवरी 2021 से बढ़ी हुई दर पर भुगतान। 6. राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों तथा यू0जी0सी0 वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों, जिन्हें सातवाँ पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किया है, को दिनांक 01 जनवरी 2022 से बढ़ी हुई दर पर मंहगाई भत्ते का भुगतान।	
3	GUJARAT	1. Grant of Temporary Increase (Dearness Relief) to State Government Pensioners / Family Pensioners with effect from Dt- 01.07.2021 (Revision of Pay Rule, 2009, 6 <sup>th</sup> Pay commission) 2. Grant of Temporary Increase (Dearness Relief) to State Government Pensioner/Family Pensioners w.e.f. Dt. 01.07.2019 (Revision of Pay Rule, 1998, 5 <sup>th</sup> Pay Commission) 3. Grant of Temporary Increase (Dearness Relief) to State Government Pensioners/ Family Pensioners with effect from Dt- 01.07.2021 (Revision of Pay Rule, 2009, 6 <sup>th</sup> Pay Commission)	1. Ref No. Govt. Resolution No.HGV-102017-O-1201-P दिनांक 18.08.2022 (196%) 2. Ref No. Govt. Resolution No.HGV-2008-500-P दिनांक 29.07.2022 (312%) 3. Ref No. Govt. Resolution No.HGV-102017-O-1201-P दिनांक 22.08.2022 (203%)
4	JAMMU & KASHMIR	1. Payment of Dearness Allowance to State Government employees on revised rate effective from- 01.01.2022 (31 to 34%)	1. Ref No. GO No. 113 दिनांक 20.04.2022
5	GOA	1. Grant of Dearness Relief to Goa State Freedom Fighter Pensioners of Government of Goa- Revised rate effective from 01.01.2022 @ 203% from 196%	1. Ref No. GO No. 11/4/2012-HD(G)/7738 दिनांक 06.09.2022
6	TELANGANA	1. Dearness Allowance- Revision of Dearness Allowance to the State Government Employees from 01.01.2020, 01.07.2020 and 01.01.2021, Payable from 1 <sup>st</sup> of July 2021 2. Public Services- Revised Pay Scales, 2020 Order-Issued 3. Dearness Allowances- Recommendations of First Pay Revision Commission- Regulation in the Revised Pay Scales, 2020- Accepted order-issued 4. Pensions-Additional Quantum of pension/FP to be Allowed to those pensioners/FP on attaining the age of 70 years and above in the pre-revised Scales of pay, 2020 Commission,	1. Ref No. GO No. 03 दिनांक 19.01.2022 2 Ref No. GO No. 51 दिनांक 11.06.2021 3. Ref No. GO No. 52 दिनांक 11.06.2021 3. Ref No. GO No. 113 दिनांक 20.10.2021

आपसे अनुरोध है, कि संलग्न शासनादेशों में निहित निर्देशानुसार उक्त दरों से, सम्बन्धित राज्य के पेंशनरों को पेंशन / पारिवारिक पेंशन में मंहगाई राहत का भुगतान देयता के आधार पर करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें एवं इस कार्यालय को भी सूचित करें। उक्त आदेशों की प्रति कोषागार के नोटिस बोर्ड में चस्पा करके व्यापक रूप से प्रचारित कर एवं अपने अधीनस्थ उप कोषागारों एवं बैंकों को भी एक प्रति प्रेषित करें।  
संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

वरि० लेखाधिकारी / पेंशन

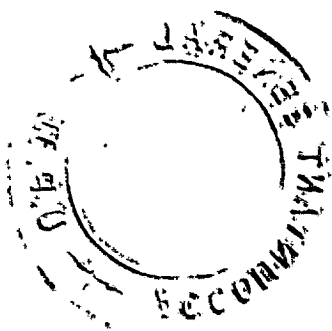
No. Pension(Misc)/ 741

dated :- 13/10/2022

~~Copy forwarded for information and necessary action to:-~~

SL.	Name of the Office & Address
1	Office of the AG (A&E) West Bengal, Treasury Buildings, No.2, Govt. Place (west) Kolkata. 700001
2	AG(A&E) Uttarakhand, Mahalekhakar Bhawan, Kaulagarh, Dehradun-248195
3	AG(A&E) Gujarat, Ahmedabad Branch, 5 <sup>th</sup> Floor, "Audit Bhavan" Navrangpura, Ahmedabad-380009
4	Office of The Principal Accountant General (A&E) -Jammu & Kashmir, M.Y. Rather Avenue, Exhibition Ground, Opp. New Sectt., Srinagar-190001
5	Directorate of Accounts Fazenda Building, Behind Old Secretariat, Panaji- Goa-403001
6	Office of the Principal Accountant General (A&E), Telangana, Hyderabad-500004
7	Director of Treasuries, Jawahar Bhawan, 10 <sup>th</sup> Floor, Lucknow 226001
8	निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी, निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ -226001
9	Sr. Accounts Officer, O/o the Accountant General (A&E)-II, Uttar Pradesh, Audit Bhawan, Vibhuti Khand, Gomatinagar, Lucknow-226010.
10	Dy. Accountant General (Pension) Cell Local.
11	Secretary to AG (A&E)-II, UP, Prayagraj

13/10/2022  
लेखाधिकारी / पेंशन



25

RG - 85145 (E)

06/09/22



कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक) गुजरात, अहमदाबाद,  
'ऑडिट भवन', पाँचवी मंजिल, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380009

विशेष मुद्रा प्राधिकार

पंजीकृत डाक द्वारा

सं पेंशन/जी.आर./विशेष मुद्रा/02,03,04,05/2022-23/जा. सं. 582 से

दिनांक : 25/08/2022

विषय:- Grant of Temporary Increase (DR) to Gujarat State Government Pensioners/Family Pensioners w.e.f. 5th, 6th, 7th Pay Commission

जा.सं	जा.सं
1 551	17 567
महालेखाकार कार्यालय I - (लेखा व हक) आंध्र प्रदेश हैदराबाद, - 500004	कार्यालय महालेखाकार, (लेखा एवं हक)-II, उत्तर प्रदेश ऑडिट भवन, विभूति खंड, गोमतीनगर, लखनऊ 226 010
2 552	18 568
महालेखाकार कार्यालय (लेखा व हक), मेघालय, शिलांग - 793 001	महालेखाकार कार्यालय (लेखा व हक), वेस्ट बंगाल कलकत्ता - 700 001
3 553	19 569
महालेखाकार कार्यालय (लेखा व हक), आसाम Maidamgaon, Beltola गौहाटी - 781 029	महालेखाकार कार्यालय (लेखा व हक), जम्मू - कश्मीर श्रीनगर - 190 009
4 554	20 570
महालेखाकार कार्यालय (लेखा व हक) -I झारखण्ड राँची - 834 002	महालेखाकार कार्यालय (लेखा व हक), मणिपुर, इम्फाल - 795 001
5 555	21 571
महालेखाकार कार्यालय (लेखा व हक) -II बिहार, गांधी मैदान, पटना - 800 00	महालेखाकार कार्यालय (लेखा व हक), त्रिपुरा, अगरतला - 799 006
6 556	22 572
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक) केरल, एम.जी.रोड, डाक थैला सं 5607, तिरुवनन्तपुरम - 695 001, केरल	महालेखाकार कार्यालय (लेखा व हक), नागालैन्ड, कोहीमा - 797 001
7 557	23 573
महालेखाकार कार्यालय (लेखा व हक), मध्यप्रदेश, ग्वालीयर - 474 002	कार्यालय महालेखाकार (ले.व.ह.) उत्तराखंड, कोलाहा, सहारनपुररोड, माजरा, देहरादून - 248 195.
8 558	24 574
महालेखाकार कार्यालय (लेखा व हक) -I तमिलनाडू चैनई - 600 018	महालेखाकार कार्यालय (लेखा व हक), छत्तीसगढ़, रायपुर - 492 111
9 559	25 575
महालेखाकार कार्यालय (लेखा व हक) -I महर्षि कर्वे मार्ग, महाराष्ट्र, मुंबई - 400 020	प्रधान महालेखाकार कार्यालय (लेखा व हक), मिज़ोरम नई कैपिटल परिसर, खातला, आइज़ोल - 796 001
10 560	26 576
महालेखाकार कार्यालय (लेखा व हक) -II वेस्ट हाईकोर्ट रोड, महाराष्ट्र नागपुर - 440 001	महालेखाकार कार्यालय (लेखा व हक), सिक्कीम, गंगटोक - 737 102
11 561	27 577
महालेखाकार कार्यालय (लेखा व हक), कर्णाटक, बेंगलुरु - 560 001	वेतन एवं लेखा अधिकारी, 5 पेन्सन दिल्ली, तीस हजारा, नई दिल्ली - 110 054
12 562	28 578
महालेखाकार कार्यालय (लेखा व हक), उड़ीशा, भुवनेश्वर - 751 001	लेखा नियंत्रक, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली - 110 001
13 563	29 579
महालेखाकार कार्यालय (लेखा व हक), पंजाब चंडीगढ़, सेक्टर - 17, पिन - 160 017	निर्देशक, लेखा एवं कोषागार, गोवा सरकार, गोवा, पणजी - 403 001
14 564	30 580
महालेखाकार कार्यालय (लेखा व हक), हरियाणा, सेक्टर-33/बी, प्लॉट-नं-4&5, चंडीगढ़ - 160 047	निर्देशक, लेखा एवं खजाना, (संघ क्षेत्र), डी.ए.टी. रोड, रंजित नगर. (D.A.T. Road, Rainbow nagar). पोंडिचेरी - 605 00
15 565	31 581
महालेखाकार कार्यालय (लेखा व हक), हिमाचल प्रदेश, सिमला - गार्टन कैसल वीलडिंग, सिमला - 171 001	निर्देशक, लेखापरीक्षा एवं पेंशन, अरुणाचल प्रदेश, नहरलागन - 791 110
16 566	32 582
महालेखाकार कार्यालय (लेखा व हक) भगवान दास रोड, राजस्थान, जयपुर - 302005.	कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक)-II, उत्तर प्रदेश, 20, सरोजिनीनाथ डगार्ग, इलाहाबाद - 211, 001 उत्तर प्रदेश

DPPF-GUJ GR:

27/49

अनुमोदित  
समर्थित  
अनुमोदित



कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक) गुजरात, अहमदाबाद, विशेष मुद्रा प्राधिकार  
'ऑडिट भवन', पाँचवी मंजिल, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380009

सं/पेंशन/जी.आर./विशेष मुद्रा/GR-02-03-04-05/2022-23/जा. सं. 582 दिनांक-: 25/08/2022

विषय: Grant of Temporary Increase (DR) to Gujarat State Government Pensioners/Family Pensioners with effect from 5<sup>th</sup>, 6<sup>th</sup>, 7<sup>th</sup> Pay Commission.

संदर्भ:- Govt. Of Gujarat, Finance Department, GR No (1) HGV-102017-O-450-P, दिनांक:-20/08/2022. (Admissible from date 01/01/2022. Admissible Rate 34% of the basic Pension 7<sup>th</sup> C.P.C. (2) HGV-2008-500-P दिनांक:- 29/07/2022 Admissible from date-01/07/2019. Admissible Rate 312% of the basic Pay 5<sup>th</sup> C.P.C. (3) HGV-102017-O-P दिनांक:- 22/08/2022. (Admissible from date-01/01/2022. Admissible Rate 203% of the basic Pension 6<sup>th</sup> C.P.C. (4) HGV-102017-O-P दिनांक:- 18/08/2022. (Admissible from date-01/07/2021. Admissible Rate 196% of the basic Pay. 6<sup>th</sup> C.P.C.)

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में वित्त मंत्रालय, गुजरात सरकार के संकल्प पत्र सं. 01 to 04 आपको प्रेषित किया जा रहा है ताकि आप इसे अपने राज्य के सभी कौषागारों/पेंशन भुगतान प्राधिकारियों को भिजवाने की व्यवस्था करें और आपके राज्य से पेंशन प्राप्त कर रहे गुजरात राज्य के सभी पेंशनरों को इसका लाभ त्वरित दिलाने का कष्ट करें.

भवदीय,

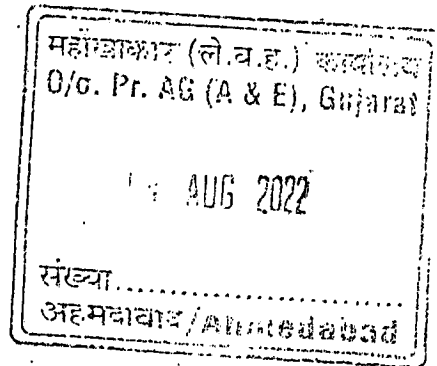
वर्णिष्ठ लेखाधिकारी/पेंशन

G.O.V.-03  
24/08/2022

Grant of Temporary Increase  
(Dearness Relief) to State  
Government Pensioners /  
Family Pensioners w.e.f. Dt.  
01/07/2019 (Revision of Pay  
Rule, 1998, 5<sup>th</sup> Pay  
Commission).

GOVERNMENT OF GUJARAT  
Finance Department,  
Govt. Resolution No. HGV-2008-500-P  
Sachivalaya, Gandhinagar.

Dated: 12.9 JUL 2022



Read:-

- (I) GR FD NO. HGV/ 2008/ 500//P, Dated: 23/10/2019.
- (II) GR FD NO. PGR/1098/8/M, Dated: 20/01/1998.
- (III) Government of India, Ministry of Finance, Department of Expenditure  
O.M.No. 1/3(2)/2008 – E –II (B), Dated: 25/10/2019.
- (IV) GR FD No. VLB-102017-GOI-2-Ch, Dated: 17/03/2020.

### RESOLUTION:

The Pensioners / Family Pensioners who are getting pension / family pension according to Pay Scales of G.C.S.R.(Revision of pay), Rule 1998 (5<sup>th</sup> Pay Commission) have been accorded temporary increase (T.I.) up to 295% vide Government Resolution as mentioned at (I) above.

2. Temporary Increase has been accorded to the pensioners who are getting pension /family pension under 5th Pay Commission as per the provision of Govt. of India, vide Office Memorandum mentioned at (III) above. Accordingly, the State Government has decided to sanction the rates of Temporary Increase w.e.f. dt.01/07/2019 admissible to the State Government's pensioners / family pensioners, who are getting pension / family pension as per Fifth Pay Commission as under :

No.	Admissible from date	Admissible Rate
1.	From 01/07/2019	312% of the basic pay

3. Payment of Temporary Increase (Dearness Relief) involving a fraction of a rupee shall be rounded off to the next higher rupee but an amount less than 50 paise shall not be paid.

4. Temporary Increase will be admissible on the amount of basic pension/ family pension plus 50% of merged Dearness Relief as per the Govt. Resolution dated : 01/09/2005.

5. The arrears of difference payable under these orders shall be paid in cash.

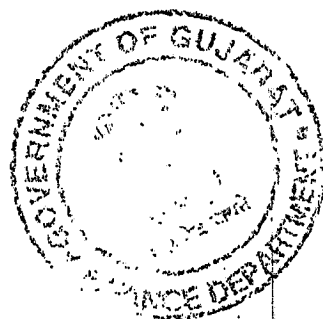
6. Other terms and conditions in the Govt. Resolutions read above shall be applicable to the pensioners/ family pensioners for the Temporary Increase.

7. It will be the responsibility of the Pension Disbursing Authority, to calculate the quantum of Temporary Increase payable in each individual case.

8. All Accountant General of the respective States/Central Administrative Authority except Gujarat State are requested to take necessary action to authorize all the disbursing authorities under their control for making payment to Gujarat Pensioners drawing pensioners from their State Treasuries, Including Public Sector Banks.

9. Concerned Board, Corporation or organization will be free to give benefits of this resolution to their employees as per their financial strength. For this purpose the State Government will not give any kind of additional grant.

By order and in the name of the Governor of Gujarat,

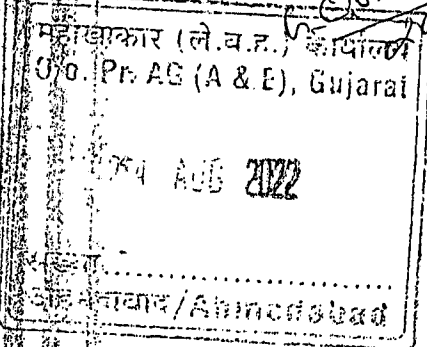


*Dipal Hadiyal*  
(DIPAL HADIYAL)  
Deputy Secretary,  
Finance Department.

To,

- The Secretary to the Hon'ble Governor, Rajbhavan, Gandhinagar,
- The Principal Secretary to Hon'ble Chief Minister, Gandhinagar.
- The Personal Secretaries to all Hon'ble Ministers / State level Ministers,
- Parliamentary Secretaries, Sachivalaya, Gandhinagar.

Grant of Temporary Increase  
(Dearness Relief) to State  
Government Pensioners /  
Family Pensioners with effect  
from Dt: 01/01/2022 (Revision  
of Pay Rule, 2009, 6<sup>th</sup> Pay  
Commission).



GOVERNMENT OF GUJARAT  
Finance Department,  
Govt. Resolution No. HGV-102017-O-1201-P  
Sachivalaya, Gandhinagar,  
Dated:22/08/2022

Read:-

- (I) GR FD NO. PGR/1009/7/Pay Cell (M), Dated: 27/02/2009.  
(II) GR FD No. PGR-102016-4 & 5- Pay Cell, Dated: 13/04/2009.  
(III) Government of India, Ministry of Finance, Department of Expenditure  
O.M.No. 1/3(1)/2008 - E -II (B), Dated: 07/04/2022.  
(IV) GR FD No. VLB-102009-GOI-10-Ch, Dated: 17/08/2022.  
(V) GR FD No. HGV-102017-O-1201-P, Dated: 18/08/2022.

**RESOLUTION:**

The Pensioners / Family Pensioners who are getting pension / family pension according to Pay Scale of G.C.S.R.(Revision of pay), Rule 2009 (6<sup>th</sup> Pay Commission) have been accorded temporary increase (T.I.) up to 196% vide Government Resolution as mentioned at (V) above.

Now, the State Government has decided to increase the rates of Temporary Increase (Dearness Relief) admissible to State Government pensioners / family pensioners, who are getting pension / family pension according to Revision of Pay Rule as under:

No.	Admissible from date	Admissible Rate
1.	From 01/01/2022	203% of the basic pension

1. Payment of Temporary Increase (Dearness Relief) involving a fraction of a rupee shall be rounded off to the next higher rupee.

2. Temporary Increase (Dearness Relief) at the rates indicated in above table will also be admissible on the additional basic pension/additional family

pension available to Pensioners/Family Pensioners based on their age as indicated in Government Resolution, Finance Department No. PGR-102016-4 & 5- Pay Cell, Dated : 13/04/2009 and Government Resolution, Finance Department, No. PGR-102016-6-Pay Cell, dated 15th October, 2016.

3. The temporary increase as 203% will be paid regularly along with monthly pension from August-2022, the difference of 7 months from January-2022 to July-2022 of the proposed temporary increase will be paid in three installments:-(1) first installment (January-2022 to March-2022) along with the pension of August-2022, (2) Second installment (April-2022 to June-2022) along with the pension of September-2022 and (3) Third installment (July-2022) along with the pension of October-2022.


4. It will be the responsibility of the Pension Disbursing Authority, to calculate the quantum of Dearness Relief payable in each individual case.

5. All Accountant General of the respective States/Central Administrative Authority except Gujarat State are requested to take necessary action to authorize all the disbursing authorities under their control for making payment to Gujarat Pensioners drawing pension from their State Treasuries, Including Public Sector Banks.

6. Other Provisions governing grant of temporary Increase (Dearness Relief) to Pensioners such as regulations of dearness relief during employment/re-employment, regulations to temporary increase (Dearness Relief), where more than one pension is drawn etc. will remain unchanged.

By order and in the name of the Governor of Gujarat,

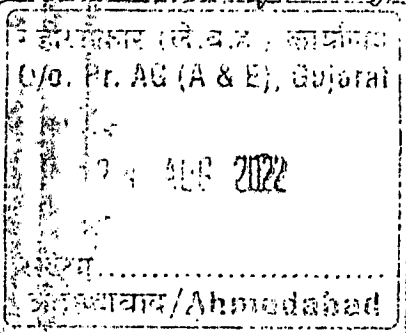


  
(Dipal Hadiyal)  
Deputy Secretary,  
Finance Department.

To,

- The Secretary to Governor of Gujarat, Raj Bhavan, Gandhinagar.  
The Personal Secretary to The Chief Minister/ All Ministers / Dy. Ministers / State Ministers / P.secretaries, Sachivalaya, Gandhinagar.  
The Personal Secretary to the Hon'ble Leader of Opposition, Gujarat Vidhansabha, Sachivalaya, Gandhinagar.
- The Secretary, Gujarat Legislative Secretariat, Gandhinagar,
- The Secretary, Gujarat Vigilance Commission, Gandhinagar,
- The Secretary, Gujarat Civil Service Tribunal, Gandhinagar,
- The Secretary, Hon'ble Gujarat High Court, Ahmedabad.
- The Secretary, Gujarat Subordinate Staff Selection Board, Gandhinagar.

Grant of Temporary Increase  
(Dearness Relief) to State  
Government Pensioners /  
Family Pensioners with effect  
from Dt: 01/07/2021 (Revision  
of Pay. Rule, 2009, 6<sup>th</sup> Pay  
Commission).



GOVERNMENT OF GUJARAT  
Finance Department,  
Govt. Resolution No. HGV-102017-O-1201-P  
Sachivalaya, Gandhinagar,  
Dated:18/08/2022

Read:-

- (I) GR FD NO. PGR/1009/7/Pay Cell (M), Dated: 27/02/2009.  
(II) GR FD No. PGR-102016-4 & 5- Pay Cell, Dated: 13/04/2009.  
(III) Government of India, Ministry of Finance, Department of Expenditure  
O.M.No. 1/3(1)/2008 – E –II (B), Dated: 13/08/2021.  
(IV) Government of India, Ministry of Finance, Department of Expenditure  
O.M.No. 1/3(1)/2008 – E –II (B), Dated: 01/11/2021.  
(V) GR FD No. VLB-102009-GOI-10-Ch, Dated: 22/09/2021.  
(VI) GR FD No. VLB-102009-GOI-10-Ch, Dated: 02/05/2022.  
(VII) GR FD No. HGV-102017-O-1201-P, Dated: 20/03/2020.

**RESOLUTION:**

The Pensioners / Family Pensioners who are getting pension / family pension according to Pay Scale of G.C.S.R.(Revision of pay), Rule 2009 (6<sup>th</sup> Pay Commission) have been accorded temporary increase (T.I.) up to 164% vide Government Resolution as mentioned at (VII) above.

Now, the State Government has decided to increase the rates of Temporary Increase (Dearness Relief) admissible to State Government pensioners / family pensioners, who are getting pension / family pension according to Revision of Pay Rule as under:

No.	Admissible from date	Admissible Rate
1.	From 01/07/2021	196% of the basic pay

1. Payment of Temporary Increase (Dearness Relief) involving a fraction of a rupee shall be rounded off to the next higher rupee.

2. Temporary Increase (Dearness Relief) at the rates indicated in above table will also be admissible on the additional basic pension/additional family pension available to Pensioners/Family Pensioners based on their age as indicated in Government Resolution, Finance Department No. PGR-102016-4 & 5- Pay Cell, Dated : 13/04/2009 and Government Resolution, Finance Department, No. PGR-102016-6-Pay Cell, dated 15th October, 2016.

3. The amount of revised Temporary Increase will be paid From AUGUST, 2022 to the State Govt. Pensioners/Family Pensioners.

4. The arrears of difference payable under these orders shall be paid in cash.

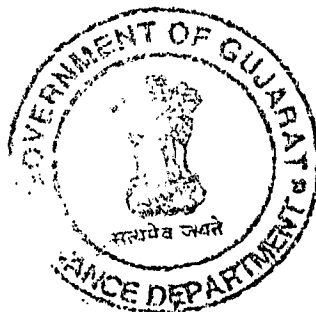
5. The rate of Temporary Increase (Dearness Relief) will remain 164% during dt.01/01/2020 to dt.30/06/2021.

6. It will be the responsibility of the Pension Disbursing Authority, to calculate the quantum of Dearness Relief payable in each individual case.

7. All Accountant General of the respective States/Central Administrative Authority except Gujarat State are requested to take necessary action to authorize all the disbursing authorities under their control for making payment to Gujarat Pensioners drawing pension from their State Treasuries, Including Public Sector Banks.

8. Other Provisions governing grant of temporary Increase (Dearness Relief) to Pensioners such as regulations of dearness relief during employment/re-employment, regulations to temporary increase (Dearness Relief), where more than one pension is drawn etc. will remain unchanged.

By order and in the name of the Governor of Gujarat,



*(Signature)*  
(Dipal Hadiyal)  
Deputy Secretary,  
Finance Department.

To,

- The Secretary to Governor of Gujarat, Raj Bhavan, Gandhinagar.  
The Personal Secretary to The Chief Minister/ All Ministers / Dy. Ministers / State Ministers / P.secretaries, Sachivalaya, Gandhinagar.  
The Personal Secretary to the Hon'ble Leader of Opposition, Gujarat Vidhansabha, Sachivalaya, Gandhinagar.
- The Secretary, Gujarat Legislative Secretariat, Gandhinagar,
- The Secretary, Gujarat Vigilance Commission, Gandhinagar,

# कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक.)-उत्तराखण्ड

## "महालेखाकार भवन" कौलागढ, देहरादून - 248195

पत्रांक: पी.ए./पेंशन/ 22-23/12/22

दिनांक: 24/10/2022

File No. FIN-7-B/1/1/2022-XXVII-7-Finance Department (Computer No. 22807)

/37010/2022

/37010/2022

संख्या-325 / XXVII(7)02/2016  
दिनांक 29 दिसम्बर, 2021

सदर आदेश

Government of Uttarakhand  
Finance (G.R.-P.C.) Section-7  
No. XXVII(7)02/2016  
Dated 24 May 2022

Office Memorandum

विषय राज्य सरकार के ऐसे सिविल/पारिवारिक पेंशनर जिनकी पेंशन सातवें पेंशन आयोग की संस्तुतियों के अंग में पुनरीक्षित की गयी है, को महंगाई राहत की स्वीकृति।

Subject: Grant of Dearness Relief to such civil/family pensioners of the State Government whose pension is revised in accordance with the recommendation of the 7th pay Commission.

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में गुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के ऐसे पेंशनर, जिनकी पेंशन सातवें पेंशन आयोग की संस्तुतियों के अंग में पुनरीक्षित की गयी है को वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-325 / XXVII(7)02/2016 दिनांक 29 दिसम्बर, 2021 द्वारा स्वीकृत महंगाई राहत की दरों को अतिक्रमण करते हुए दिनांक 01-01-2022 से 31 प्रतिशत के स्थान पर 34 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

The Undersigned is directed to say that the Governor is pleased to revise the Dearness Relief rates w.e.f. 01-01-2022 @ 34% instead of 31 % superseding the earlier rates as is sanctioned vide this Office Memorandum No. 325/XXVII(7)02/2016 Dated 29 December, 2021 for those pensioners whose pension is revised in accordance with the recommendation of the 7th pay Commissions.

2. यह आदेश गा0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा प्रायोजनिक उपक्रम आदि के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों पर स्वतः लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

These orders will not be applicable to the judges of High Court, Chairman and Members of Uttarakhand Public Service Commission, Civil/Family Pensioners of local bodies and Public Undertaking Corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective department.

3. यह आदेश विद्यालयी शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

These orders will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from State under the Education/Technical Education Department whose Pension/Family Pension is at par with the pensioners of the State Government.

4. शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-1-252/दस/10(3)-81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के सिद्धे महालेखाकार को प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः स्वीकृत महंगाई राहत का भुगतान उक्त कार्यालय ज्ञाप 3 के अन्तर्गत कर दिया जाय।

As per orders issued in O.M. No-A-1-252/X/10(3)-81, dated April 27, 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment, of dearness relief as admissible under, this O.M.

5. महंगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य अधिसूचनाओं को इस आदेश में इससे पूर्व निर्गत आदेशों में निर्धारित के, सम्बन्धित लागू रहेंगे।

Other terms and conditions regarding of dearness relief laid down in earlier government orders shall remain applicable as usual.

(सौजन्या)  
सचिव।

(Sowjanya)  
Secretary

BY SPEED POST/REGISTERED POST/SPECIAL MESSENGER

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E), WEST BENGAL  
TREASURY BUILDINGS, KOLKATA - 700 001.

Circular No. Pen. Co-ordn./Bihar/Vol.- IX/DR/71

Date.: 15-07-2022

*Subject : Grant of Dearness Relief to the Bihar Government pensioners/family pensioners with effect from 01-01-2022.*

In continuation to this office circular No. Pen. Co-ordn./Bihar/Vol.- IX/DR/151 dated 24-01-2022, this is to state that the Government of Bihar in their FD Resolution No. 3A-3-Allowance-01/2022-3024/B. dated 08-04-2022 has sanctioned dearness relief to their pensioners/family pensioners whose pension have been revised in the light of Bihar Government FD Resolution Nos. B. (27)Pe.Co.-(Re.)22/2017-381 dated 23-05-2017 and B. (27)Pe.Co.-(Rev.)22/2017-755 dated 20-10-2017 (circulated under Nos. . Pen. Co-ordn./Bihar/Vol.- IX/Revision/63 dated 13-07-2017 and Pen. Co-ordn./Bihar/Vol.- IX/Revision-Detail/191 dated 19-01-2018), at the rate and from the date as under :-

Date of effect	Rate of Dearness Relief per month
01-01-2022	34% of basic pension/family pension

2. Payment of dearness relief involving fraction of 50 paise and above may be rounded off to the next higher rupee and fraction less than 50 paise may be ignored.

3. Dearness relief will be admissible to the civil pensioners who are getting compensatory pension, old age pension, retiring pension and invalid pension. This relief is also admissible to the pensioners getting provisional pension/family pension and extra ordinary pension.

4. Dearness relief will not be admissible at present to the re-employed pensioners. The matter will be communicated on receipt of reply from the Accountant General (A&E), Bihar.

5. So far as application of this order in respect of the retired employees of the High Court/Bihar Legislative Assembly/Bihar Legislative Council is concerned, necessary orders will be issued separately by the respective secretariat/office after obtaining the concurrence of the Chief Justice, Patna High Court/Speaker, Bihar Legislative Assembly/Chairman, Bihar Legislative Council, Bihar, Patna.

6. Incidentally, it may be mentioned that this circular is issued to other Accountants General just to remind them the applicability of this order to the West Bengal Government pensioners/family pensioners guided by Bihar Pension Rules.

7. Having been authorised by the Accountant General (A&E), Bihar in their authority No. Pen-09-709 dated 28-06-2022, followed by authority No. Pen-9-740 dated 07-07-2022, it is requested to make necessary arrangement for payment of dearness relief @ 34% with effect from 01-01-2022 to all eligible Bihar Government pensioners/family pensioners as well as West Bengal Government pensioners/family pensioners guided by Bihar Pension Rules on their revised pension/family pension mentioned above after proper adjustment of dearness relief.

8. The charges on this account for the pensioners/family pensioners of Government of Bihar are debitable to the Government of Bihar under the head "8793-I.S.S.A/cs.; Government of Bihar etc." and the charges for the West Bengal Govt. pensioners/family pensioners guided by Bihar Pension Rules are debitable to the Government of West Bengal under the head "2071-Pension and Other Retirement Benefits".

Receipt of the circular may please be acknowledged.

Gr. D/1503  
04/08/22

ACCOUNTANT GENERAL (A&E)

Sr. Accounts Officer

Uttam Pradham

Lucknow. 22606

P.T.O.

**Sub:-Ex-gratia grant for the year 2021-22 to the pensioners/family pensioners of Ex-Management Staff of North Bengal Medical College& Burdwan Medical College**

It is informed that the Govt. of West Bengal Higher Education Department, Budget Branch in their Memo no.62-Edn(B)/IM-12/2008, dated 19/05/2022 have sanctioned, ex-gratia grant for the year 2021-22, @Rs.2700/- (Rupees Two thousand seven hundred) only in lump per head to the pensioners of State Aided Universities including the holders of provisional pension who retired prior to 30/9/2021 and also the pensioners who retired or died after 30/9/2021 but prior to 1/9/2022 and whose basic pension plus relief on pension as on March 31<sup>st</sup> 2022 did not exceed 32,000/- (Rupees Thirty two Thousand) only and are not entitled to receive ad-hoc bonus.

The aforesaid benefit will also be admissible to the pensioner/family pensioner who retired/died in harness as Ex-Management Staff of North Bengal Medical College or Burdwan Medical College who opted for University Pension Rules and whose pension/family pension has been regulated either under G.O. No. 83-Edn(U)/84-Edn(U)/85-Edn(U) all dated 30/1/2000 or G.O. No. 464-Edn(U) dated 13/8/2010 (communicated under this office circular No.Pen.Co-ordn/258/Vol-II/228 dated 3/2/2012 and Pen. Co-ordn. /217/Vol -II/220 dated 21/12/2012).

The aforesaid benefit will not, however, be admissible to the pensioners/family pensioners who are entitled to get ad-hoc bonus and those who are employed/re-employed under any public sector undertaking/statutory bodies under the Govt. are in receipt of bonus or ex-gratia payment for the year 2020-21.

The payment of ex-gratia as sanctioned in the Memo may be made to the Muslim Pensioners/family pensioners immediately on receipt of this circular and other than Muslim Pensioners/Family pensioners, the payment in this regard may be disbursed in between 19<sup>th</sup> September 2022 to 23<sup>rd</sup> September 2022.

Accordingly, all Pension Disbursing Officers are requested to make necessary arrangements for payment of Ex-gratia @ Rs. 2700/- (Rupees Two thousand and seven hundred only) to all eligible pensioners/family pensioners who retired/died in harness as Ex-Management Staff of North Bengal Medical College or Burdwan Medical College and whose P.P.O.s bear the indication "University Pension Rules", subject to fulfillment of the conditions mentioned above.

  
Sr.Accounts Officer



प्रधान महालेखाकार का कार्यालय (लेखा व हकदारी)  
तेलंगाणा, हैदराबाद - 500004  
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E)  
Telangana Hyderabad - 500 004

Lr. No.PM-OGP/VI/2022-23/TS-GO's/Circular/SSA No.1191/33/902 Dt: 07-09-2022

सेवा मे/To  
The Accountant General (A&E),  
Uttar Pradesh, 20, Sarojini Naidu Marg,  
ALLAHABAD - 211 001.

महोदय/Madam/Sir,

विषय/Sub:- Pensions - 4 GO's 03, 51, 52 & 113 of Telangana Govt.

- 1) Dearness Allowance - Revision of Dearness Allowance to the State Government Employees from 1.1.2020, 1.7.2020 and 1.1.2021, payable from 1 st of July, 2021.
- 2) PUBLIC SERVICES - Revised Pay Scales, 2020 - Orders - Issued.
- 3) Dearness Allowance - Recommendations of First Pay Revision Commission - Regulation in the Revised Pay Scales, 2020 - Accepted - Orders -Issued.
- 4) Pensions - Additional Quantum of pension/FP to be allowed to those pensioners/FP on attaining the age of 70 years and above in the Pre-Revised Scales of Pay, 2020 Commission. Orders Issued.

संदर्भ/Ref:- GO Ms. Nos.03, 19.01.2022, 51 Dt.11.06.2021, 52  
DT:11.06.2021, & 113 DT: 20.10.2021 of Finance  
(HRM.V)Department, Government of Telangana.

\*\*\*

I am to enclose herewith copies of Telangana Govt. / G.O.Ms.Nos.3, 51, 52 and 113. The same are placed in the website of this office <https://cag.gov.in/ae/telangana/en/page-ae-telangana-telangana-rpr>. You are requested to direct all the District Treasury Officers to download the orders and take necessary action at the earliest to minimize hardship to the pensioners.

संलग्नक/Encl: यथोपरि/As above

आपका विश्वसनीय/Yours faithfully,

वरिष्ठ लेखा अधिकारी/Senior Accounts Officer

Phone : 040-23236810 - 19

Fax No : 040-23232441

Email : [agaeandhrapradesh@cag.gov.in](mailto:agaeandhrapradesh@cag.gov.in)

Website : <http://agaeapts.gov.in>

5  
2  
4  
1  
3

1  
2  
3  
4

1

2

3

4

1 1 1

1

( ) 2, 1, 1 / ( ) 1, 1, 1 /

1

1

1



**GOVERNMENT OF TELANGANA**

**ABSTRACT**

**ALLOWANCES** – Dearness Allowance – Revision of Dearness Allowance to the State Government Employees from 1.1.2020, 1.7.2020 and 1.1.2021, payable from 1<sup>st</sup> of July, 2021 – Sanctioned – Orders – Issued.

**FINANCE (HRM.IV) DEPARTMENT**

G.O.Ms.No.3

Dated: 19<sup>th</sup> January, 2022

Read the following: -

1. G.O.Ms.No.73, Law (LA&J, SC-F) Department, dated: 01.05.2010.
2. G.O.Ms.No.171, Finance (PC.III) Department, dated: 13.05.2010.
3. G.O.Ms.No.88, Finance (HRM.IV) Department, dated: 06.11.2019.
4. G.O.Ms.No.69, Finance (HRM.IV) Department, dated: 20.10.2020.
5. G.O.Ms.No.51, Finance (HRM.IV) Department, dated: 11.6.2021.
6. G.O.Ms.No.52, Finance (HRM.IV) Department, dated: 11.6.2021.
7. O.M.No.1/1/2020-E.II(B), dated: 23.4.2020 of Department of Expenditure, Ministry of Finance, Government of India.
8. O.M.No.1/1/2020-E.II(B), dated: 20.7.2021 of Department of Expenditure, Ministry of Finance, Government of India.

& & &

**ORDER:**

Government hereby order revision of the Dearness Allowance (DA) sanctioned in the Government Order 6<sup>th</sup> read above to the employees of Government of Telangana from **7.28%** of basic pay to **17.29%** of basic pay with monetary benefit from 1<sup>st</sup> of July, 2021. This increase subsumes the instalments of Dearness Allowance arising on 1.1.2020, 1.7.2020 and 1.1.2021. The Dearness Allowance for the period from 1.1.2020 till 30.6.2021 shall remain at 7.28% only in the Revised Pay Scales, 2020.

2. The above revision of Dearness Allowance shall also be applicable to;

- a) The employees of Zilla Parishads, Mandal Parishads, Gram Panchayats, Municipalities, Municipal Corporations, Agricultural Market Committees and Zilla Grandhalaya Samasthas, Work Charged Establishment, who are drawing pay in a regular scale of pay in the Revised Pay Scales, 2020.
- b) Teaching and Non-Teaching Staff of Aided Institutions including Aided Polytechnics who are drawing pay in a regular scale of pay in the Revised Pay Scales, 2020.
- c) Teaching and Non-Teaching Staff of Universities who are drawing pay in a regular scale of pay in the Revised Pay Scales, 2020.

3. Government also hereby order revision of the Dearness Allowance sanctioned vide reference 4<sup>th</sup> read above, to the State Government employees, who are drawing pay in the Revised Pay Scales, 2015 from 38.776% of the basic pay to 51.876% of the basic pay with monetary benefit from 1<sup>st</sup> of July, 2021. This increase subsumes the instalments of Dearness Allowance arising on 1.1.2020, 1.7.2020 and 1.1.2021. The Dearness Allowance for the period from 1.1.2020 till 30.6.2021 shall remain at 38.776% only in the Revised Pay Scales, 2015.

4. The Dearness Allowance sanctioned in the para-3 above shall also be payable to;

- a) The employees of Zilla Parishads, Mandal Parishads, Gram Panchayats, Municipalities, Municipal Corporations, Agricultural Market Committees, Zilla Grandhalaya Samasthas and Work Charged Establishment, who are drawing pay in a regular scale of pay in the Revised Pay Scales, 2015.
- b) Teaching and Non-Teaching Staff of Aided Institutions including Aided Polytechnics who are drawing pay in a regular scale of pay in the Revised Pay Scales, 2015.
- c) Teaching and Non-Teaching Staff of Universities who are drawing pay in a regular scale of pay in the Revised Pay Scales, 2015.

5. Government hereby order revision of Dearness Allowance from 17% to 28% of basic pay, with monetary benefit from 1<sup>st</sup> July, 2021 in respect of the following categories of employees. This increase subsumes the instalments of Dearness Allowance arising on 1.1.2020, 1.7.2020 and 1.1.2021. The Dearness Allowance for the period from 1.1.2020 till 30.6.2021 shall remain at 17% only in the Revised U.G.C./AICTE Pay Scales, 2016.

- a) The Teaching staff of Government and Aided Affiliated Degree Colleges who are drawing pay in the Revised U.G.C Pay Scales, 2016.
- b) The Teaching staff of the Universities and the Teaching staff of the Government Polytechnics, who are drawing pay in the Revised UGC/AICTE Pay Scales, 2016.

6. Government hereby order revision of Dearness Allowance from 164% to 189% of basic pay with monetary benefit from 1<sup>st</sup> July, 2021 in respect of the following categories of employees. This increase subsumes the instalments of Dearness Allowance arising on 1.1.2020, 1.7.2020 and 1.1.2021. The Dearness Allowance for the period from 1.1.2020 till 30.6.2021 shall remain at 164% only in the Revised U.G.C./AICTE Pay Scales, 2006.

- a) The Teaching staff of Government and Aided Affiliated Degree Colleges who are drawing pay in the Revised U.G.C Pay Scales, 2006.
- b) The Teaching staff of the Universities and the Teaching staff of the Government Polytechnics, who are drawing pay in the Revised UGC/AICTE Pay Scales, 2006.

7. Government also hereby order revision of Dearness Allowance in respect of Judicial Officers whose pay scales were revised as per Government orders issued vide reference 1<sup>st</sup> read above, from 164% to 189% of the basic pay with monetary benefit from 1<sup>st</sup> July, 2021. This increase subsumes the additional installments arising on 1.1.2020, 1.7.2020 and 1.1.2021 and the rate of Dearness Allowance for the period from 1.1.2020 till 30.6.2021 shall remain at 164% only in the Revised Judicial Pay Scales, 2006.

8. Government also hereby order revision of Dearness Allowance to all the full time/contingent employees whose remuneration has been revised from Rs.3,850/- to Rs.6,700/- per month vide Government order 2<sup>nd</sup> read above, as per Revised Pay Scales, 2010, with effect from 1<sup>st</sup> July, 2021 @9.416% (i.e.  $11 \times 0.856 = 9.416\%$ ) of the pay and at cumulative rate of 136.0844%.

9. Government also hereby sanction an ad-hoc increase of Rs.100/- per month to the Part-Time Assistants and Village Revenue Assistants from 1<sup>st</sup> of July, 2021.

10. The Dearness Allowance sanctioned in the paras. 1-9 above shall be paid along with the salary of January, 2022 payable on 1<sup>st</sup> of February, 2022.

11. The arrears on account of payment of Dearness Allowance for the period from 1<sup>st</sup> of July, 2021 to 31<sup>st</sup> December, 2021 shall be credited to the General Provident Fund Account of the respective employees. However, in the case of employees who are due to retire on or before 30<sup>th</sup> of April, 2022, the arrears of Dearness Allowance shall be drawn and paid in cash as the employees due to retire on superannuation are exempted from making any subscription to the General Provident Fund during the last four months of service.

12. In respect of the employees who were appointed to Government service on or after 01.09.2004 and are governed by the Contributory Pension Scheme (CPS), 10% of the Dearness Allowance arrears from 1<sup>st</sup> July, 2021 to 31<sup>st</sup> December, 2021, shall be claimed and credited to the PRAN accounts of the individuals along with the Government share as per the existing orders. The remaining 90% of Dearness Allowance arrears shall be paid in three (03) equated monthly instalments starting from May, 2022, payable from 1<sup>st</sup> June, 2022.

13. In respect of Full Time Contingent Employees, who are not eligible for GPF Accounts, the arrears may be paid along with the salary for the month of April, 2022, payable on 1<sup>st</sup> of May, 2022.

14. In the event of death of any employee before the issue of these orders, the legal heir(s) shall be entitled to the arrears of Dearness Allowance in lumpsum.
15. The term 'Pay' for this purpose shall be as defined in F.R.9 (21) (a) (i).
16. All the Drawing Officers shall prefer the bill to the Pay & Accounts Officer, Hyderabad or to the Pay & Accounts Officer/ Assistant Pay & Accounts Officer of the Telangana Works Accounts Service or to the District /Assistant /Sub Treasury Officer, as the case may be, for the amount of arrears for the period from 1<sup>st</sup> of July, 2021 to 31<sup>st</sup> of December, 2021 to be adjusted to the General Provident Fund Account in the case of an employee who has opened a General Provident Fund Account.
17. The Drawing Officers shall ensure that the bills are supported by proper schedules in duplicate indicating details of the employee, the General Provident Fund Account Number and the amount to be credited to the General Provident Fund Account, to be submitted to the Pay & Accounts Officer/District Treasury Officers/Assistant Pay & Accounts Officers or Pay & Accounts Officers of the Telangana Works Accounts Service, as the case may be. The Pay & Accounts Officer/Assistant Pay & Accounts Officer or Pay and Accounts Officer of the Telangana Works Accounts Service/District Treasury Officer/Assistant/Sub-Treasury Officer shall follow the usual procedure of furnishing one copy of the schedules along with bills to the Accountant General based on which the Accountant General shall credit the amounts to the General Provident Fund Accounts of the individuals concerned. The second copy of the schedules shall be furnished to the Drawing Officers with Voucher Numbers.
18. In respect of employees working in Government Offices in the Twin Cities, the Pay and Accounts Officer, Hyderabad and in respect of employees working in other Government Offices, the Director of Treasuries and Accounts and the Director of Works Accounts, concerned shall consolidated and furnish the information in the proforma prescribed at Annexure-I, appended to this order to the Finance (HRM.IV) Department. In respect of employees of Local Bodies, the Director of State Audit, shall furnish the consolidated information to the Finance (HRM.IV) Department.

19. All the Drawing and Disbursing Officers and Audit Officers are requested to intimate to the employees working under their control as to how much amount of arrears of Dearness Allowance is credited to the General Provident Fund Account/Compulsory Savings Account as per the Proforma annexed in Annexure-II, appended to this order. They are further requested to adhere to the above instructions and any deviation or non-compliance of these instructions will be viewed seriously.

20. The expenditure on the Dearness Allowance to the employees of Agricultural Market Committees and Greater Hyderabad Municipal Corporation shall be met from their own funds in view of the orders issued in G.O.Ms.No.9, Finance (PC-I) Department, dated: 18.01.2010.

21. All Departments of Secretariat and Heads of Departments are requested to issue suitable instructions to the Drawing and Disbursing Officers under their control and to see that these instructions are followed scrupulously. The Director of Treasuries and Accounts/Director of Works Accounts/Director of State Audit/Pay and Accounts Officer, Hyderabad, are requested to issue suitable instructions to their subordinate officers so as to compliance these orders.

22. This Government Order is available on Internet and can be accessed at the address <http://goir.telangana.gov.in>.

**(BY ORDER AND IN THE NAME OF THE GOVERNOR OF TELANGANA)**

**K.RAMAKRISHNA RAO,**  
SPECIAL CHIEF SECRETARY TO GOVERNMENT

To  
All Special Chief Secretaries/Principal Secretaries/Secretaries to Government,  
Telangana Secretariat, Hyderabad.  
All Head of Departments, Government of Telangana.  
All District Collectors/Superintendents of Police of Telangana.  
The Director of Treasuries & Accounts, Telangana, Hyderabad.  
The Director of State Audit, Telangana, Hyderabad.  
The Pay & Accounts Officer, Telangana, Hyderabad.  
The Principal Accountant General (Audit-I/II/A&E), Telangana, Hyderabad.

The Secretary to Governor of Telangana, Hyderabad.  
The Principal Secretary to the Chief Minister and Private Secretaries to all Ministers.  
The Registrar General (Admin), High Court of Telangana, Hyderabad.

Copy to:

All the Chief Executive Officers of all Zilla Parishads.

All the Recognized Service Associations.

The Registrar of all the Universities.

The General Administration (Cabinet) Department, Telangana Secretariat,  
Hyderabad.

SF/SCs.

//forwarded by order//

**SECTION OFFICER**

**ANNEXURE-I**

(to G.O.Ms.No.3, Finance (HRM.IV) Department dated:19.01.2022)

1. Name of the Sub-Treasury/  
District Treasury/Audit Officer. ::
2. The amount of arrears of D.A.  
credited to G.P.F. Accounts ::
3. The amount of arrears of D.A.  
credited to Compulsory savings  
Account. ::
4. Total amount of arrears of D.A.  
credited to the G.P.F. Accounts  
And credited to Compulsory  
Savings Account. ::

Date:  
Office Seal

Signature of the Audit Authority

**ANNEXURE-II**

(to G.O.Ms.No.3, Finance (HRM.IV) Department dated:19.01.2022)

1. Name of Office ::
2. Designation of the Drawing and  
Disbursing Officer, ::
3. Name and Designation of the employee. ::
4. Whether the amount of arrears credited  
to the General Provident Fund Account/  
Compulsory Savings Accounts. ::
5. The amount of arrears of D.A.  
so credited to G.P.F. Account/  
Compulsory Savings Account. ::

Date:  
Office Seal

Signature of the Drawing and  
Disbursing Officer



**GOVERNMENT OF TELANGANA  
ABSTRACT**

**PUBLIC SERVICES – Revised Pay Scales, 2020 – Orders – Issued.**

**FINANCE (HRM,IV) DEPARTMENT**

G.O.Ms.No.51

Dated: 11<sup>th</sup>, June, 2021  
Read the following:-

1. G.O.Ms.No.25, Finance (HRM,IV) Department, dated:18.03.2015.
2. G.O.Ms.No.86, General Administration (Spl.A) Department,  
Dated: 18.05.2018.
3. G.O.Ms.No.36, Finance (HRM,IV) Department, dated:1.6.2019.

8&8

**ORDER:**

In the Government order second read above, orders were issued constituting the 1<sup>st</sup> Pay Revision Commission. The Pay Revision Commission has submitted its report to the Government on 31.12.2020 and recommended, inter alia, the following in regard to Revised Pay Scales and fixation of pay in the Revised Pay Scales;

- a) To continue the concept of Master Scale.
- b) A revised master scale of Rs.19000 – 640 – 20920 – 660 – 22900 – 690 – 24970 – 720 – 27130 – 750 – 29380 – 830 – 31870 – 940 – 34690 – 1030 – 37780 – 1110 – 41110 – 1190 – 44680 – 1280 – 48520 – 1400 – 52720 – 1500 – 57220 – 1630 – 62110 – 1730 – 67300 – 1850 – 72850 – 1990 – 78820 – 2140 – 85240 – 2270 – 92050 – 2420 – 99310 – 2560 – 106990 – 2760 – 115270 – 2960 – 124150 – 3160 – 133630 – 3420 – 147310 – 3690 – 162070 (80).
- c) To continue the existing (32) grades and (80) segments of the Revised Master Scale.
- d) To merge the Dearness Allowance as on 01.07.2018, i.e., 30.392% sanctioned vide Government order third read above, in the pay.
- e) A fitment benefit of 7.5% for fixing the pay in the Revised Pay Scales.
- f) To sanction five stagnation increments beyond the time scale in all grades in the event of stagnation.

g) The Revised Pay Scales should come into force from 1.7.2018 and as regard giving monetary benefit the Government may take a view on the date from which the financial benefit would accrue keeping in view its resources and the demands on those resources.

2. Government have constituted a three members committee with Chief Secretary as Chairman and Principal Secretaries to Government, Finance Department and Irrigation and Command Area Development Department as Members, to obtain the views of various service associations on the recommendations of the Pay Revision Commission. The Committee has conducted group wise meetings with various service associations in a phased manner in regard to implementation of the major recommendations of the Pay Revision Commission and submitted its report to Government.

3. Government, after careful consideration of the matter, have decided to implement the recommendations of the Pay Revision Commission mentioned in Para 1 above, subject to the modification that the fitment benefit for fixation of pay in the revised pay scales shall be 30% instead of 7.5% recommended by the Pay Revision Commission and accordingly order the following on the Revised Pay Scales and fixation in the Revised Pay Scales, 2020;

- i The Revised Master Scale shall be Rs.19000 – 640 – 20920 – 660 – 22900 – 690 – 24970 – 720 – 27130 – 750 – 29380 – 830 – 31870 – 940 – 34690 – 1030 – 37780 – 1110 – 41110 – 1190 – 44680 – 1280 – 48520 – 1400 – 52720 – 1500 – 57220 – 1630 – 62110 – 1730 – 67300 – 1850 – 72850 – 1990 – 78820 – 2140 – 85240 – 2270 – 92050 – 2420 – 99310 – 2560 – 106990 – 2760 – 115270 – 2960 – 124150 – 3160 – 133630 – 3420 – 147310 – 3690 – 162070 (80).
- ii The existing (32) Grades shall continue with (80) segments in the Revised Master Scale.
- iii The Revised Scales of Pay shall be as set out in Schedule-I to the Notification appended to this order against each of the corresponding existing pay scales specified therein. These scales shall be common to all the employees in various categories except where specified otherwise in the Departmental Pay Schedule as shown in Schedule-II, appended to the Notification. Holders of posts not included in Schedule-II will be governed by the Revised Pay Scales corresponding to the present scales as shown in the Schedule-I.
- iv The requests for any further revision of pay scales for the categories already included in the Schedule-II shall not be entertained in any case.
- v A fitment benefit of 30% shall be given for fixing the pay in the Revised Pay Scales, 2020.
- vi The dearness allowance of 30.392% as on 1.7.2018 shall be merged in the pay as recommended by the Pay Revision Commission.
- vii The Revised Pay Scales, 2020 shall be deemed to have come into force on and from 01.07.2018.

viii) The monetary benefit shall be allowed from 01.04.2020.

ix) The arrears for the period from 01.04.2020 to 31.03.2021 shall be paid at the time of superannuation of the Government employee or to the legal heirs in case of demise of the employee.

x) The arrears for the period from 01.04.2021 to 31.05.2021, will be paid during the financial year 2021-22.

xi) The salary in the Revised Pay Scales, 2020, will be paid from the month of June, 2021 payable in July, 2021.

4. The Pay of the employee in the Revised Pay Scales, 2020 shall be fixed with effect from 01.07.2018 or any other subsequent date in accordance with the option exercised as per the rules in the appended Notification. The Rules for exercise of option and fixation of pay in the Revised Pay Scales are notified in the Notification appended to this order.

5. The Revised Pay Scales shall apply to -

- a. all employees of the State Government;
  - b. the employees of the Local Bodies and Aided Institutions including Aided Polytechnics, who are in receipt of pay in a regular pay scale in the Revised Pay Scales of 2015; and
  - c. the Work-charged Establishment in receipt of pay in a regular pay scale in the Revised Pay Scales of 2015.
6. Wherever statutory Notifications are required to be issued for applying these orders to the employees other than Government employees, the Administrative Departments of the Secretariat concerned, shall issue such notifications in consultation of Finance (HRM.IV) Department.

7. Separate orders will be issued in regard to Officers and Staff of the High Court of Judicature at Hyderabad for the State of Telangana.

8. The Revised Pay Scales, 2020 will not be applicable to;

- a) the teaching and other staff in Government Colleges, including Medical Colleges, Government Aided Private Colleges who are drawing pay in the Revised UGC/ICAR/AICTE Pay Scales.
- b) to the officers of the Telangana State Higher Judicial Service and Telangana State Judicial Service who are governed and covered by the recommendations of the First National Judicial Pay Commission and subsequent pay revisions.

c) the persons who were re-employed before 1<sup>st</sup> of July, 2018 and are continuing on re-employment beyond that date.

d) the employees of Industrial and Commercial undertakings of the Government, Contingent Establishment both full time and part time and employees who are engaged on contract and/or on out sourcing basis.

9. In respect of employees of Public Sector Undertakings, Corporations, Co-operative Societies and other such institutions under Government, the concerned administrative department shall obtain specific orders of the competent authority in consultation of Public Enterprises and Finance (HRM.IV) Departments, duly following the Business Rules, in respect of each such entity.

10. In respect of employees who are already enjoying the benefits of Automatic Advancement Scheme, the Pay shall be fixed in the corresponding revised scales of Automatic Advancement Grades in accordance with these instructions.

11. Government also hereby orders that all the employees falling under Grade-I to Grade-XXXII are entitled for five (05) stagnation increments beyond the time scale in the Revised Pay Scales, 2020. These stagnation increments shall be treated as increments for all purposes such as fixation of pay on promotion, Automatic Advancement Scheme and Pension.

12. The above orders are issued in so far as the recommendations relating to the scales of pay, pay fixation and other related matters are concerned. Separate orders will be issued covering the other recommendations of the Pay Revision Commission regarding Dearness Allowance, House Rent Allowance, Additional House Rent Allowance in lieu of rent-free quarters, City Compensatory Allowance and other Allowances, Special Pays, Automatic Advancement Scheme, Loans and Advances, Pension, terminal benefits and other related matters.

13. All Drawing Officers shall take immediate action for fixing the pay of all Gazetted and Non-Gazetted Officers whose pay and allowances are drawn by Heads of Offices in their substantive as well as officiating posts. In the case of Heads of Departments, the pay shall be fixed by the Pay and Accounts Officer, Hyderabad under intimation to the administrative department of the Secretariat concerned.

14. The following Notification shall be published in the Telangana Gazette:

#### **NOTIFICATION**

**In exercise of the powers conferred by the Proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Telangana hereby makes the following rules, namely;**

**1. Short title, commencement and application:**

- I. These rules may be called the Telangana Revised Scales of Pay Rules, 2020.
- II. The Revised Scales shall be deemed to have come into force on the 1<sup>st</sup> of July, 2018.
- III. These rules shall apply to all the Government employees whether temporary, regular or permanent appointed before 1<sup>st</sup> of July, 2018.

## 2. Definitions:

In these rules, unless the context otherwise requires;

1. Basic pay means pay as defined in Fundamental Rule 9 (21) (a) (i).
2. existing emoluments means the aggregate of:
  - a. (i) the basic pay, including the stagnation increments if any, in the existing scale of pay as on 1<sup>st</sup> of July, 2018 or on any other date of entry into the Revised Pay Scales, 2020 according to clause (b) of sub rule (1) of rule 5;
  - (ii) personal pay sanctioned under Rule 9 (23) (a) of the Fundamental Rules or Rule 7 (40) (a) of the Hyderabad Civil Service Rules, as the case maybe;
  - (iii) personal pay sanctioned in pursuance of proviso (ii) under rule 6 (b) of the Revised Scales of Pay Rules, 2015 to the extent such personal pay has not been absorbed in increases in pay on promotion till the date of entry into the Revised Pay Scales, 2020.

b. Dearness allowance admissible at the rate which existed on the 1<sup>st</sup> of July, 2018 appropriate to the basic pay referred to in sub-rule 2 (a) (i);

3. existing scales of pay means the Revised Pay Scales, 2015;
4. Revised Pay Scales, 2020 means the Revised Pay Scales set out in column (4) in Schedule-I or in column (4) in Schedule-II, as the case may be.

## 3. Revised Pay Scales, 2020:

- 1) Except as otherwise provided in sub-rule- (2), the existing scales of pay specified in column (2) of Schedule-I shall be revised as specified in the corresponding entry in column (4) of the said schedule.
- 2) Where, in the case of any post on an existing scale of pay specified in column (2) of Schedule-I, a revised scale of pay, other than the revised scale of pay specified in the corresponding entry in column (4) of Schedule I, is specified in column (4) of Schedule-II, the revised scale of pay so specified in column (4) of Schedule-II shall apply.

## 4. Date of entitlement to the Monetary Benefit:

No Government employee who enters into the Revised Pay Scales, 2020 before 01.04.2020 shall be entitled to any monetary benefit for any period prior to that date.

## 5. Principles for exercising option:

- (1) Subject to other provisions of this rule, a Government employee holding a post under the Government on 1<sup>st</sup> July, 2018, the scale of which is revised, may opt:

- (a) to remain in the existing scales of pay, or
- (b) to draw pay in the Revised Pay Scales, 2020 either from 1<sup>st</sup> of July, 2018 or from the date on which he earns his next increment in the existing scales of pay, but not beyond 30.06.2019.

- (c) Employees whose date of increment in the existing scales of pay happens to be 01.07.2018 shall be allowed option to get their pay fixed in the Revised Pay Scales, 2020 as indicated below:

Either based on the pay in the existing scales of pay as on 01-07-2018 excluding the increment which is due on 01-07-2018.

OR

Based on the pay in the existing scales of pay including the increment due on 01-07-2018.

- (2) A Government employee, who is entitled to exercise option under sub-rule (1) shall do so within a period of 6 (six) months from the date of publication of these rules in the Telangana Gazette. The option once exercised shall be final.

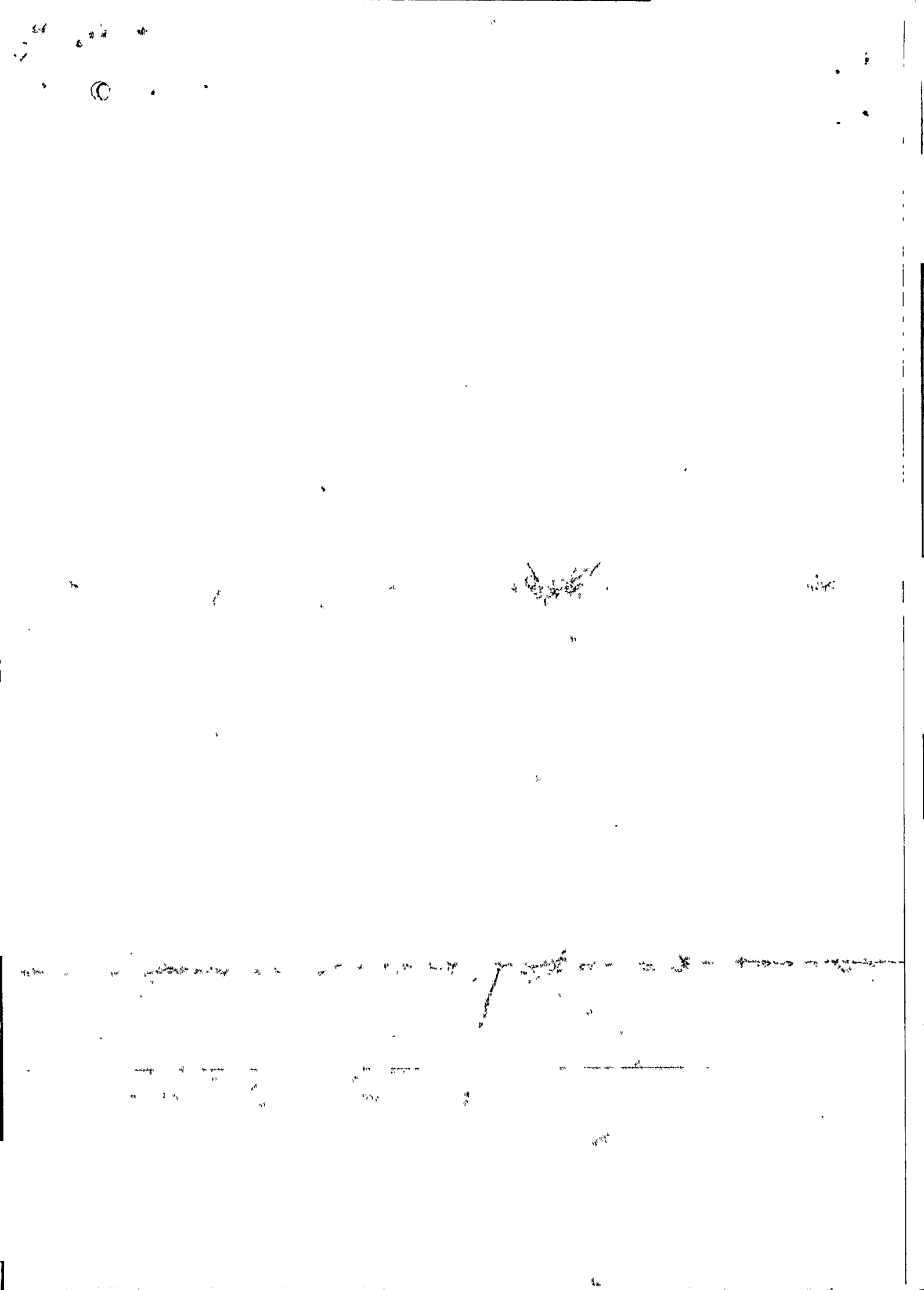
(3)

- (a) If a Government employee does not exercise his option in writing within the time specified in sub-rule (2), he shall be deemed to have opted to the Revised Pay Scales, 2020 from 01-07-2018.

- (b) If a Government employee exercises option to enter into the Revised Pay Scales, 2020 from a date beyond 30-06-2019, such option shall be deemed to be invalid and shall be governed by sub-rule (3) (a) of this rule.

- (4) A Government employee shall exercise his option in respect of the post held by him on the 1<sup>st</sup> July, 2018 and also, in respect of each of the lower posts which he would have held on that day but for his holding the higher posts.

- (5) Every Government employee shall exercise his option in writing in the form specified in the Annexure and shall communicate it in triplicate to;



GOVERNMENT OF TELANGANA  
ABSTRACT

[illegible]

FINANCE (HRM.V) DEPARTMENT

U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE  
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION  
WASHINGTON, D. C. 20535

# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

1944-1945

- 4 G.O. Ms No 100, Finance (HRM-V) Department, dated: 06.04.2019  
5 G.O. Ms No 53, Higher Education (UE-IV) Department, dated: 08.06.2011  
6 G.O. Ms NO 54, Higher Education (UE-IV) Department, dated: 08.06.2011  
7 G.O. Ms No 100, Finance (HRM-V) Department, dated: 21.07.2015  
8 G.O. Ms NO 22, Finance (HRM-V) Department, dated: 11.06.2011  
9 DTA L/NO 11/2661/2021, dated: 30.06.2021

1998

In the reference 4<sup>th</sup> read above, orders were issued sanctioning additional quantum of Pension/ Family Pension for the State Government Pensioners/ Family Pensioners, in partial modifications of the recommendations made by the First Pay Revision Commission.

2. In the reference 6<sup>th</sup> read above, the Director of Treasuries and Accounts, sought clarification on the applicability of the orders issued vide reference 5<sup>th</sup> read above to the University / Government / Aided Retired teachers who are drawing the UGC/AICTE Pay Scales.

3. Government after careful examination of the matter, issue the following amendment to the G.O. 5<sup>th</sup> read above:

## Amendment

4. In para 4 of G.O.Ms.No.57, Finance (HRM-V) Department, dated 11.06.2021, after the words "State Government Pensioners / Family Pensioners", the words "Retired University / Government / Aided Retired teachers, who are drawing UGC/ AICTE Pay Scales in the State and all Non-Government Service Pensioners, whose service Pension is being charged to MH-2071 Pensioners and other retirement benefits" shall be inserted.

5. The Director of Treasuries and Accounts, shall take necessary action in the matter, accordingly.

The Government Order is available on Internet and can be accessed at the  
address <http://www.doit.telangana.gov.in>  
and <http://www.finance.telangana.gov.in>

**(BY ORDER AND IN THE NAME OF THE GOVERNOR OF TELANGANA)**

**K. RAMAKRISHNA RAO  
SPECIAL CHIEF SECRETARY TO GOVERNMENT**

To,  
All Special Chief Secretaries / Principal Secretaries / Secretaries to Government,  
Telangana Secretariat, Hyderabad;  
The Director of Treasuries and Accounts Officer, Telangana, Hyderabad;  
The Pay and Accounts Officer, Telangana, Hyderabad;  
The Accountant General, Telangana, Hyderabad;  
Registers of All Universities of Telangana;  
All Special Chief Secretaries / Principal Secretaries / Secretaries to Government,  
Andhra Pradesh Secretariat;  
The Director of Treasuries and Accounts Officer, Andhra Pradesh;  
The Pay and Accounts Officer, Andhra Pradesh;  
The Accountant General, Andhra Pradesh;  
Registers of All Universities of Andhra Pradesh;  
SF/SCs

**//FORWARDED BY ORDER//**

*Varadachari*  
**SECTION OFFICER**



## GOVERNMENT OF TELANGANA

### ABSTRACT

**ALLOWANCES – Dearness Allowance** - Recommendations of First Pay Revision Commission – Regulation in the Revised Pay Scales, 2020 – Accepted - Orders – Issued.

### FINANCE (HRM.IV) DEPARTMENT

G.O.Ms.No.52

Dated: 11<sup>th</sup> June, 2021

Read the following:-

1. G.O.Ms.No.26, Finance (HRM.IV) Department, dated:18.03.2015.
2. G.O.Ms.No.86, General Administration (Spl.A) Department, dated:18.05.2018.
3. G.O.Ms.No.36, Finance (HRM.IV) Department, dated:01.06.2019.
4. G.O.Ms.No.88, Finance (HRM.IV) Department, dated: 06.11.2019.
5. G.O.Ms.No.69, Finance (HRM.IV) Department, dated: 23.10.2020.
6. G.O.Ms.No.51, Finance (HRM.IV) Department, dated:11.06.2021.

&&&

### ORDER:

In the Government Order second read above, orders were issued constituting the 1<sup>st</sup> Pay Revision Commission. The Pay Revision Commission has submitted its report to the Government on 31.12.2020.

2. The Pay Revision Commission, inter alia, recommended the following on Dearness Allowance:

*"The Dearness Allowance be regulated at 0.910% for the State Government Employees and Pensioners for every one percent (01%) of Dearness Allowance sanctioned to the Employees and Pensioners of Government of India with effect from 01.01.2019."*

3. Government have accepted the above recommendation of the Pay Revision Commission. Accordingly, it is hereby ordered that the Dearness Allowance to the State Government Employees shall be regulated @ 0.910% for every one percent (01%) of Dearness Allowance sanctioned to the Employees and Pensioners of Government of India, with effect from 01.01.2019.

4. The Dearness Allowance already sanctioned in the Revised Pay Scales, 2015, vide Government Orders 4<sup>th</sup> and 5<sup>th</sup> read above shall be regulated in the Revised Pay Scales, 2020 as under:

Date of effect	Rates of Dearness Allowance sanctioned by the Government of India (In 7 <sup>th</sup> CPC)	Rate of Dearness Allowance to State Government Employees and Pensioners in Revised Pay Scales, 2020	
		Dearness Allowance	Cumulative Dearness Allowance
01.01.2019	3% (12-9)	2.73%	2.73%
01.07.2019	5% (17-12)	4.55%	7.28%

5. These orders are applicable to:

- All employees of the State Government;
- All employees of the Local Bodies and Aided Institutions including Aided Polytechnics, who are drawing pay in a regular pay scale in the Revised Pay Scales, 2020, and
- The Work-charged establishment who are drawing pay in a regular pay scale in the Revised Pay Scales of 2020.

6. These orders are not applicable to:-

- Employees who opt to remain in the Revised Pay Scales, 2015;
- Teachers working in the Universities, Affiliated Degree Colleges both under Government and Aided management who are drawing pay in the Revised UGC/ICAR/AICTE Pay Scales; and
- All India Services Officers.
- Higher Judicial Service and State Judicial Service employees who are governed by the First National Judicial Pay Commission and subsequent pay revisions.

7. The Dearness Allowance shall be claimed along with the pay fixation in the Revised Pay Scales, 2020 and the Dearness Allowance already sanctioned in the Government Orders issued vide reference 4<sup>th</sup> and 5<sup>th</sup> read above, shall be notionally adjusted up-to 31.3.2020. The arrears from 1.4.2020 to 31.3.2021 shall be paid at the time of superannuation of the Government employee or to the legal heirs in case of demise of the employee. The arrears for the period from 01.04.2021 to 31.05.2021, will be paid during the financial year 2021-22. The revised rates of Dearness Allowance shall be paid along with the salary in the Revised Pay Scales, 2020 from the month of June, 2021 payable in the month of July, 2021.

8. This Government Order is available on Internet and can be accessed at the address <http://goir.telangana.gov> in and <http://finance.telangana.gov.in>.

**(BY ORDER AND IN THE NAME OF THE GOVERNOR OF TELANGANA)**

**K. RAMAKRISHNA RAO  
PRINCIPAL SECRETARY TO GOVERNMENT**

To

All Special Chief Secretaries / Principal Secretaries / Secretaries to Government, Telangana Secretariat, Hyderabad.  
All Heads of Departments, Government of Telangana, Hyderabad.  
All District Collector & Magistrates, Telangana.  
All District Superintendent of Police, Telangana.  
The Director of Treasuries and Accounts, Government of Telangana, Hyderabad.  
The Director of Works and Accounts, Government of Telangana, Hyderabad.  
The Director of State Audit, Government of Telangana, Hyderabad.  
The Pay and Accounts Officer, Hyderabad.  
The Principal Accountant General (Audit-I), Telangana, Hyderabad.  
The Principal Accountant General (Audit-II), Telangana, Hyderabad.  
The Accountant General (A & E), Telangana, Hyderabad.  
The Registrar General,  
High Court of Judicature at Hyderabad for the State of Telangana.  
The Chairman and Managing Director,  
Telangana TRANSCO, Telangana GENCO, Vidyuthoudha, Hyderabad.  
The Secretary, Telangana Public Service Commission, Hyderabad.  
The Vice Chairman and Managing Director,  
Telangana State Road Transport Corporation, Hyderabad.  
The Registrar of all Universities, Telangana.

**Copy to:**

The Secretary to Hon'ble Governor, Telangana, Hyderabad.  
The Principal Secretary to Hon'ble Chief Minister, Government of Telangana.  
The Private Secretaries to Hon'ble Ministers, Government of Telangana.  
P.S. to Chief Advisor/Advisor (Finance).  
O.S.D. to Chief Secretary.  
P.S. to Prl. Finance Secretary/Secretary, Finance/Spl. Secretary, Finance.  
P.S. to Senior Consultant (HR), Finance Department.  
The General Administration (Cabinet/SW) Department,  
Telangana Secretariat, Hyderabad.  
SF/SCs.

**//FORWARDED BY ORDER//**

**SECTION OFFICER**

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Government of Goa  
Directorate of Accounts

Fazenda Building, Behind Old Secretariat, Panaji – Goa. 403 001

[EPABX Nos. 2225531/21/48, 2226381, 2224069(Ext. 228, 207)] Fax No. 2226410

Email: aopa1-acco.goa@nic.in,

website. [www.accountsgoa.gov.in](http://www.accountsgoa.gov.in)

BY SPEED POST

UNDER SPECIAL SEAL

No. DA/DA.II/Pens/22-23/TR- 6118 / DR- 1579

Dated: 21/9/2022

Sub: - Grant of Dearness Relief to Goa State Freedom Fighter Pensioners of Government of Goa-Revised rate effective from 01/01/2022 @ 203%, from 196%.

1. The Government of Goa, Department of Home (General); Secretariat, Porvorim-Goa, vide letter No. 11/4/2012-HD(G)/7738 dated 06<sup>th</sup> September 2022 have conveyed the sanction for revision of Dearness Relief to Goa State Freedom Fighters. The copy of the said letter is enclosed for information and necessary action.
2. Since the order on relief contained in the above Government of Goa's Letter are applicable to Goa Government Freedom Fighters and Goa Freedom Fighter Family Pensioners under Freedom Fighter Welfare Rules, 2013, I am to authorize you to pay to the Goa Government Freedom Fighters Pensioners/Family Pensioners the installment of 7% of Dearness Relief raising it from 196% to 203% with effect from 01/01/2022.
3. In case of Goa State Freedom Fighters/Family Pensioners drawing pension in other States, the instructions contained in above Letter may be issued to all the Treasuries/Sub-Treasuries/P.A.O where they are drawing their monthly pension.
4. This Dearness Relief is only applicable to the Goa State Freedom Fighter Pensioners/ Family Pensioners.
5. Instructions issued from time to time by this office as regards to payment of relief should be observed.
6. Wide Publicity may be given to this circular letter by displaying a copy on the office notice board or other permanent place in your office.
7. Pensioners who have drawn part payment of their pension through Treasury Office after 01/07/2016 and have subsequently opted for payment of their pension through Bank may also be paid arrears without waiting for any individual orders from this office.
8. The receipt of this letter may please be acknowledged.

14. Dy. Controller of Accounts Central Controlling Accounting Officer, Tircoot – 11,  
Complex Bhikaji Kama Palace, Behind Hotel, Hyatt Regency, New Delhi – 110 006
15. Department of Audit, Scientific and Commercial Dept. No. 101, M.K. Rd. Mumbai – 20.
16. Director of Audit (Central), Madhu Industrial Estate, Pandurang Budhkar Marg., Worli  
Mumbai – 400 013.
17. Director of Audit (Central) Old Currency Bldg. No. 1, B.D.O. Bag Kolkata 700 001.
18. Pay and Accounts Office, No. 5, Tis Hazari – Delhi.
19. The Asstt. Accounts Officer, Directorate of Accounts, Diu.
20. The Director of Audit, Central Revenue, Indraprashta Estate, New Delhi 10 002.
21. The Director of Audit and Pension, Government of Arunachal Pradesh, Naharlagun.
22. Government of Mizoram, Directorate of Accounts & Treasuries, Mizoram, Aizwal.
23. Sr. Deputy Accountant General (pension) Office of the Accountant General (A&E)  
Uttarkhand Oberai Motors Building, Saharanpur Road, Majra Dehradun – 248171.
24. Office of the Resident Commissioner, Government of Goa, Goa Sadan, 18 Amrita  
Shergil Marg, New Delhi 110003 - ----- Copy for information.

Pension / control



9306

Government of Goa  
DEPARTMENT OF HOME (GENERAL)  
SECRETARIAT  
Porvorim-Goa

Tel. No. (0832) - 2419775

Email: usgen-home.goa@nic.in

No.11/4/2012-HD(G) 7738

Dated:-06/09/2022

To,  
The Director of Accounts,  
Directorate of Accounts,  
Panaji-Goa.

Subject : Regarding Dearness Allowance to the Goa State  
Freedom Fighter Pensioners

Sir,

I am directed to refer to the above subject and to state that the Government of Goa is paying monthly pension to freedom fighters registered with the State Home Department as a mark of respect for their selfless contribution to the freedom struggle of Goa. The said pension was being paid as a lump sum amount of Rs. 6000/- upto 31.03.2013. However w.e.f. 01/04/2013, the pension payment has been linked with dearness allowance as per the D.A. rates announced by Central Government and as adopted by Government of Goa vis-a-vis State Government employees.

The revised pattern of payment of pension to freedom fighters/family pensioners under the Goa Freedom Fighter Welfare Rules, 2013 is as under:-

Sr. No.	Description	Amount	Dearness Allowance
1	Basic Monthly Pension	3500/-	1) 132% to 136% (i.e. 4%) w.e.f. 01-01-2017.
2	Add Dearness Allowance	DA at the rate announced by Central Government and adopted by the State Government vis-a-vis Government employees.	2) 136% to 139% (i.e. 3%) w.e.f. 01-07-2017. 3) 139% to 142% (i.e. 3%) w.e.f. 01/01/2018. 4) 142% to 148% (i.e. 6%) w.e.f. 01-07-2018. 5) 148% to 154% (i.e. 6%) w.e.f. 01/01/2019.

2030  
12/9/22  
Sl/klh  
12/9/22

Cal  
12/9

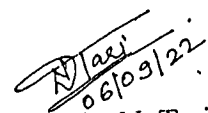
3	Add Fixed Medical Allowance	Rs. 1000/-	6) 154% to 164% (i.e. 10%)w.e.f. 01/07/2019. 7) 164% to 189% (i.e. 25%)w.e.f. 01/07/2021. 8) 189% to 196% ( i.e. 7%) w.e.f. 01/07/2021. 9) 196% to 203% ( i.e. 7%) w.e.f. 01/01/2022.
---	-----------------------------	------------	--

In this connection, Government has approved for release of Dearness Relief to the Goa Freedom Fighters from 196% to 203% w.e.f. 01/01/2022.

You are therefore requested to direct all Banks/Pension disbursing authorities for payment of freedom fighters pension under the Freedom Fighters Welfare Rules, 2013. It is also requested that future pension payments may please be revised as and when the dearness relief rate is enhanced.

This issues with the concurrence of Finance (R&C) Department vide their U.O. No. 1400085783 dated 25/08/2022.

Yours faithfully

  
 ( Diksha N. Tari )  
 Under Secretary (Home-II)

Copy to:-

- 1) The Dy. Director (Pension), Directorate of Accounts, Panaji-Goa.
- 2) The Dy. Director(Pension), Directorate of Accounts, Margao-Goa.
- 3) The Sr. Deputy Accountant General(Audit), RAO, Porvorim-Goa.
- 4) The President of Goa Daman and Diu, Freedom Fighters Association, Azad Gomantak Dal Memorial Hall, Panaji-Goa.
- 5) The President of Freedom Fighter Association, Ground floor, Gaunekar Building, Shanti Nagar, Ponda-Goa-403401.
- 6) Guard file.
- 7) Office Copy.



भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग  
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT  
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)  
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E),  
जम्मू व कश्मीर, श्रीनगर  
JAMMU & KASHMIR, SRINAGAR



GOVERNMENT OF JAMMU AND KASHMIR  
FINANCE DEPARTMENT  
Civil Secretariat, Srinagar/Jammu

\*\*\*

Subject: Payment of Dearness Allowance to State Government Pensioners/Family Pensioners - revised rate effective from 01.07.2018.

Reference: State Administrative Council decision No 81/12/2018 dated 12.09.2018.

Government Order No: 390 -F of 2018  
Dated: 13.09.2018.

In continuation to Government Order No. 224-F of 2018 dated 24-04-2018, it is hereby ordered that State Government Pensioners/Family Pensioners shall be allowed Dearness Allowance on Pension/ Family pension as under:-

Existing Rate of D.A	Revised Rate of D.A per month	Date from which applicable
7% of Basic Pay	9% of Basic Pay	01.07.2018

- (i) The enhanced pension shall be paid w.e.f October, 2018 onwards alongwith arrears from July, 2018 to September, 2018;
- (ii) The payment of Dearness Allowance involving a fraction of 50 paisa and above shall be rounded to the next higher rupee and the fraction of less than 50 paisa shall be ignored; and
- (iii) Other provisions governing the grant of Dearness Allowance on pension / family pension such as the regulation of Dearness Allowance during employment/ re-employment, where more than one pension is drawn etc. and other provisions of the existing rules / orders (as are not in conflict with the

*[Signature]*





GOVERNMENT OF JAMMU AND KASHMIR  
FINANCE DEPARTMENT

Civil Secretariat, Srinagar/Jammu

\*\*\*

Subject: Payment of Dearness Allowance to State Government Pensioners/Family Pensioners - revised rate effective from 01.01.2019.

Reference: State Administrative Council decision No 66/7/2019 dated 28.02.2019.

Government Order No: 185 -F of 2019

Dated: 07.03.2019.

In continuation to Government Order No. 390-F of 2018 dated 13-09-2018, it is hereby ordered that State Government Pensioners/Family Pensioners shall be allowed Dearness Allowance on Pension/ Family pension as under:-

Existing Rate of D.A	Revised Rate of D.A per month	Date from which applicable
9% of Basic Pay	12% of Basic Pay	01.01.2019

- (i) The arrears on account of enhanced instalment @3% D.A w.e.f January, 2019, shall be paid in cash to the State Government Pensioners and family pensioners in the month of April, 2019, and shall form part of pension/family pension there onwards.
- (ii) The payment of Dearness Allowance involving a fraction of 50 paise and above shall be rounded to the next higher rupee and the fraction of less than 50 paise shall be ignored; and
- (iii) Other provisions governing the grant of Dearness Allowance on pension / family pension such as the regulation of Dearness Allowance during employment/ re-employment, where more than one

185  
713





**GOVERNMENT OF JAMMU AND KASHMIR**  
**FINANCE DEPARTMENT**

Civil Secretariat, Srinagar/Jammu

\*\*\*

**Subject: Payment of Dearness Allowance to State Government employees - revised rate effective from 01.07.2019.**

**Reference: State Administrative Council decision No 270/22/2019 dated 22/10/2019**

**Government Order No: 456 -F of 2019**  
**Dated: 24.10.2019.**

In continuation to Government Order No. 184-F of 2019 dated 07-03-2019, it is hereby ordered that State Government employees working in regular Pay Levels under 7th Pay commission recommendations, shall be paid Dearness Allowance as under:-

Existing Rate of DA per month	Revised Rate of DA per month	W.e.f.
12% of Basic Pay	17% of Basic Pay	01.07.2019

- (i) The term 'Basic Pay' in the revised pay structure means the pay drawn in the prescribed Level in the Pay Matrix as per 7th Pay Commission recommendations, but does not include any other type of pay like special Pay etc.
- (ii) The arrears on account of additional installment @5% w.e.f. July, 2019 shall be paid in cash to the State Government Employees in November 2019 and shall form part of the monthly salary from November, 2019 onwards.
- (iii) In respect of employees on NPS, employer's share of 10% of DA arrears too shall be drawn and with equivalent amount as employees share, shall be deducted at source for crediting the same to the respective PRAN Numbers.
- (iv) Consequent upon implementation of 7th Pay Commission Recommendations in favour of All India Service Officers, serving in connection with affairs of the State, the rate of Dearness Allowance as applicable to Central Government Employees shall be applicable to such Officers.
- (v) The payment of Dearness Allowance involving a fraction of 50 paise and above shall be rounded to the next higher rupee and the fraction of less than 50 paise shall be ignored.

**By Order of the Government of Jammu & Kashmir.**

**Sd/-**

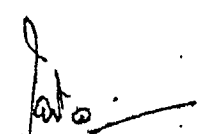
**(A. K. Mehta), IAS,**  
**Financial Commissioner,**  
**Finance Department.**  
**Dated 24.10.2019**

**No. A/24(2k)-IV-1060**

**Copy to the:-**

1. Advocate General, J&K High Court Srinagar/Jammu.
2. All Financial Commissioners.

3. Financial Commissioner with the Hon'ble Governor.
4. Principal Accountant General J&K Srinagar/Jammu.
5. All Principal Secretaries to Government.
6. Principal Resident Commissioner, 5-Prithvi Raj Road New, Delhi.
7. Chief Electoral Officer, J&K.
8. All Commissioner/Secretaries to Government.
9. Divisional Commissioner Kashmir/ Jammu/ Ladakh
10. Chief Vigilance Commissioner, J&K.
11. Principal Secretary to Chief Justice J&K High Court Srinagar/Jammu.
12. Registrar General, J&K High Court Srinagar/Jammu.
13. Director Anti Corruption Bureau, J&K.
14. Director General Accounts and Treasuries.
15. Director General, Audit and Inspections
16. Director General, J&K Funds Organization.
17. Director General, Budget Division J&K.
18. Director Local Fund Audit & Pensions, J&K.
19. Director Information J&K.
20. All Head of Departments/ Managing Directors/ Chief Executives of State PSU's/ Autonomous Bodies/ Societies.
21. Secretary J&K Public Service Commission.
22. Secretary, J&K Legislative Assembly.
23. All Directors of Finance/Financial Advisors & CAOs.
24. General Manager, Govt. Press, Srinagar/ Jammu for publication in Government Gazette.
25. Private Secretary to Hon'ble Advisor (K)/(G)/(S)/(KS)/(F), for information.
26. Private Secretary to Chief Secretary.
27. Private Secretary to Financial Commissioner, Finance Department.
28. All Treasury Officers.
29. President Jammu & Kashmir Civil Secretariat Non-Gazetted Employees Union, Jammu/Srinagar.
30. I/C website, FD ([www.jakfinance.nic.in](http://www.jakfinance.nic.in)).
31. I/C website, GAD ([www.jkgad.nic.in](http://www.jkgad.nic.in)).
32. Government Order File (W2scs).

  
**(S.L. Pandita),**  
 Director Codes,  
 Finance Department.

6

**Government of Jammu and Kashmir  
Finance Department (Codes Division)  
Civil Secretariat, Jammu/Srinagar.**

\*\*\*\*\*

**Subject:- Payment of Dearness Allowance to Pensioners/Family Pensioners on revised rate effective from 01.07.2021.**

**Reference:- General Administration Department's UO No.GAD-CORD/113/2021 DATED 01.08.2021.**

**Government Order No. 204-F of 2021**

**Dated: 02-08-2021**

In continuation to Government Order No. 457-F dated 24-10-2019, it is hereby ordered that Government Pensioners/Family Pensioners shall be, allowed Dearness Allowance on Pension/Family Pension as under:-

Existing Rate of DA per month	Revised Rate of DA per month	With effect from
17% of Basic Pension/ Basic Family Pension	28% of Basic Pension/ Basic Family Pension	01.07.2021

- (i) The increase subsumes the additional installments arising on 01.01.2020, 01.07.2020 and 01.01.2021. The rate of Dearness Allowance for the period from 01.01.2020 till 30.06.2021 shall remain at 17%.
- (ii) The payment of Dearness Allowance involving a fraction of 50 paise and above shall be rounded to the next higher rupee and the fraction of less than 50 paise shall be ignored; and
- (iii) Other provisions governing the grant of Dearness Allowance on pension/family pension such as the regulation of Dearness Allowance during employment/re-employment, where more than one pension is drawn etc. and other provisions of the existing rules/orders (as are not in conflict with provisions of the order), shall continue to remain in force.

**By order of the Lieutenant Governor.**

Sd/-

(Dr. Arun Kumar Mehta), IAS,  
Financial Commissioner,  
Finance Department.

Dated : 02-08-2021

No. : FD-Code/269/2021- 771

Copy to the:

1. Advocate General, J&K High Court Srinagar/Jammu.



2

**Government of Jammu and Kashmir  
Finance Department (Codes Division)  
Civil Secretariat, Jammu/Srinagar.**

\*\*\*\*\*

**Subject: Revision of Dearness Allowance to Pensioners/Family Pensioners revised rate effective from 01.07.2021.**

**Reference: General Administration Department's UO No. GAD-COORD/113/2021 Dated 16.11.2021.**

**Government Order No. 305 -F of 2021**

**Dated: 17-11-2021**

In continuation to the Government Order No 204 -F of 2021 Dated: 02-08-2021, it is hereby ordered that Government Pensioners/Family Pensioners shall be allowed Dearness Allowance on Pension/ Family Pension as under:-

Existing Rate of DA per month	Revised Rate of DA per month	With Effect From
28% of Basic Pension/ Basic Family Pension	31% of Basic Pension/ Basic Family Pension	01.07.2021

- 16
- 17
- i. The arrears on account of additional installment of Dearness Allowance with effect from July, 2021 shall be paid in cash to Government Pensioners and Family Pensioners in the month of November, 2021 and shall form part of Pension/family Pension from November, 2021 onwards.
  - ii. The payment on account of Dearness Allowance involving fractions of 50 paise and above may be rounded to the next higher rupee and the fractions of less than 50 paise may be ignored.
  - iii. Other provisions governing the grant of Dearness Allowance on pension/family pension such as the regulation of Dearness allowance during employment/re-employment, where more than one pension is drawn etc. and other provisions of the existing rules/orders(as are not



**Government of Jammu and Kashmir  
Finance Department (Codes Division)  
Civil Secretariat, Jammu/Srinagar.**

\*\*\*\*\*

**Subject:-Payment of Dearness Allowance to Government employees on revised rate effective from 01.01.2022.**

**Reference:-General Administration Department's File No. GAD-CORD/113/2021-09-GAD.**

**Government Order No: 113 -F of 2022**

**Dated: 20/04/2022**

In continuation to Government Order No 304-F of 2021 dated 17.11.2021, it is hereby ordered that Government employees working in regular pay levels under 7<sup>th</sup> Pay Commission recommendations shall be paid Dearness Allowance as under:-

Existing Rate of DA per month	Revised Rate of DA per month	With effect from
31% of Basic Pay	34% of Basic Pay	01.01.2022

- The term 'Basic Pay' in the revised pay structure means the pay drawn in the prescribed level in the Pay Matrix as per 7<sup>th</sup> Pay Commission recommendations, but does not include any other type of pay like special pay etc.
- The arrears on account of additional installment of Dearness Allowance with effect from January, 2022 shall be paid in cash in the month of April, 2022.
- The payment on account of Dearness Allowance involving fractions of 50 paise and above may be rounded to the next higher rupee and the fractions of less than 50 paise shall be ignored.

**By order of the Lieutenant Governor.**

**Sd/-  
(Atal Dulloo), IAS,  
Financial Commissioner,  
(Additional Chief Secretary),  
Finance Department  
Dated:-20.04.2022**

**No:- FD-Code/269/2021-02-650**

**Copy to the:-**

- Advocate General J&K High Court Srinagar/Jammu.

